

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

5 दिसम्बर, 2019

“मौजूदा आर्थिक मंदी के लिए एक बहु-आयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।”

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद) 4.5 प्रतिशत थी। सकल मूल्यवर्धित (जीवीए), जो वास्तव में आर्थिक गतिविधियों का अधिक प्रतिनिधि है, में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष की दूसरी तिमाही की वृद्धि वर्ष 2013 के चौथी तिमाही के बाद सबसे कमजोर रही है।

वर्तमान मंदी की विशिष्ट विशेषताएँ हैं जो इसे अतीत में आई मंदी से अलग बनाती हैं। सबसे पहला, कई विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र जैसे खपत, निवेश, निर्यात, क्रेडिट, सभी धीरे-धीरे कम हो गए हैं। पहली तिमाही की तरह, मंदी का अनुमानित स्रोत विनिर्माण क्षेत्र था लेकिन निवेश खर्च भी एक प्रमुख कारक रहा मंदी के लिए एवं विकास को बढ़ावा देने वाले कारक भी काफी शांत थे।

घरेलू उपभोक्ता खर्चों में मामूली संशोधन किया गया था लेकिन यह उच्च सरकारी खर्च का एक परिणाम भी हो सकता है। दूसरा, जहाँ एक तरफ पिछली मंदी आपूर्ति की कमी के परिणामस्वरूप थी, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान मंदी माँग में कमजोरी के कारण थै। अभी ध्यान वास्तविक विकास मंदी पर दिया जा रहा है लेकिन सबसे अधिक समस्या वाली बात यह है कि नोमिनल जीडीपी विकास दर में मंदी है। पिछले तीन वर्षों में वृद्धि दर में कमी और मुद्रास्फीति की बदलती गतिशीलता को देखते हुए वास्तविक विकास में 2.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में, Q2FY20 (एक साल पहले समान तिमाही में) में मामूली वृद्धि 6.1 प्रतिशत तक सीमित रही। यह चिंता का विषय है क्योंकि मामूली वृद्धि आर्थिक कारकों, उपभोक्ताओं, बचतकर्ताओं और निवेशकों के व्यवहार को आकार देती है। समान रूप से नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए इसके निहितार्थ हैं क्योंकि कई आर्थिक चर नाममात्र के विकास पर निर्भर करते हैं - उदाहरण के लिए सबसे तत्काल प्रभाव केंद्र के कर राजस्व में मंदी है।

विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र बेहतर है। जहाँ जून 2018 की तिमाही में इंडस्ट्री की ग्रोथ 10 फीसदी से गिरकर Q2 में -0.5 फीसदी पर पहुँच गई, वहीं सर्विसेज सेक्टर में मामूली 7.5 फीसदी से 6.4 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई। इस निरंतर मंदी के बारे में चिंता निर्माण और विशेष रूप से परिवहन, सेवा क्षेत्र के लिए विनिर्माण मंदी की वजह से है। निजी खपत वृद्धि सार्वजनिक डेटा के आधार पर पहली तिमाही के रूप में ऑटो बिक्री और सेवा कंपनियों के परिणामों की तरह ही कम (या कम) रहने की संभावना है।

तीसरा, पहले की मंदी वास्तविक क्षेत्र के कारण लग रही थी। इस बार समस्याएँ वित्तीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं और बेन बर्नानके के वित्तीय त्वरक के मॉडल के समान तंत्र के माध्यम से वास्तविक क्षेत्र में फैल गई हैं। क्रेडिट संकुचन ने उपभोग और निवेश को कम करने वाले कारकों को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आरबीआई के आंकड़ों ने इस साल के पहले छह महीनों में अप्रैल-सितंबर 2018 में 7.4 लाख करोड़ रुपये से लेकर कई ऋण देने वाले चैनलों के फंड के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई। अक्टूबर में बैंक क्रेडिट ग्रोथ घटकर 8.5 फीसदी रह गई है। वृद्धि में पुनरुत्थान के लिए एक स्पष्ट मार्ग तुरंत नहीं है। दूसरी तिमाही की वृद्धि सबसे कम होने की संभावना थी, फिर भी तीसरी तिमाही में एक पुनरुत्थान के शुरुआती संकेत मामूली हैं।

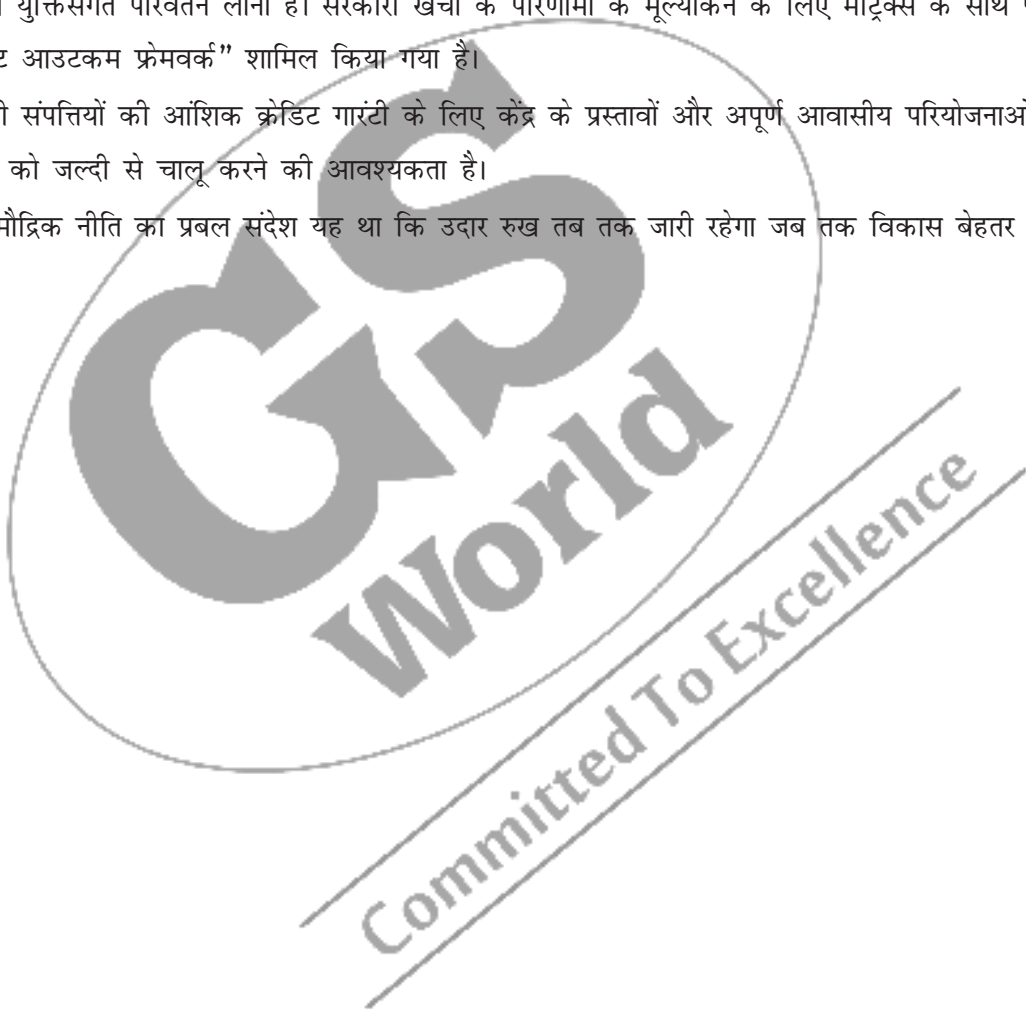
मौद्रिक नीति पहला प्रत्युत्तर था जिसमें कई रेपो रेट में कटौती शामिल थी, जो 1.35 प्रतिशत अंक तक थी और आने वाले समय में एक और कटौती की संभावना बढ़ गई है। जून तक एक बड़ी तरलता घाटे सहित कई कारणों से, बैंक जमा की लागत अधिक रहती है, इन कटौती का बैंक ऋण दरों में प्रसारण सीमित था। हालांकि, जुलाई से अधिशेष तरलता के उद्भव ने फिक्स्ड डिपॉजिट दरों में कटौती की गति को तेज कर दिया है और बैंक ऋण दरों में तेजी से वृद्धि हुई। यह एमपीसी बैठक दर में कटौती और आगे कटौती की गुंजाइश, साथ ही वृद्धि और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान पर उधार दरों का मार्गदर्शन करेगी।

बढ़ती क्षमता के लिए खपत की माँग के पुनरुद्धार का एक पुण्य चक्र शुरू करने के लिए, निजी क्षेत्र की माँग में कमजोरी को देखते हुए सरकारी खर्च महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति के साथ समन्वय में सरकार को सक्रिय रूप से एक जवाबी चक्रीय राजकोषीय प्रोत्साहन को अपनाना चाहिए। एक राजस्व स्रोत जिसका पता लगाया गया है, वह विनिवेश है। इससे कर राजस्व में कुछ कमी आ सकती है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018 तक, विभिन्न करों से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये अटक गए हैं, जिनमें से लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपये मुकदमेबाजी के अधीन थे। इसका जल्द से जल्द निपटान किया जाना चाहिए।

अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है, जैसे लक्ष्यीकरण वितरण के माध्यम से व्यय को अधिक कुशल बनाना और खर्च में युक्तिसंगत परिवर्तन लाना है। सरकारी खर्चों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए मेट्रिक्स के साथ पहली बार FY20 बजट में “आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क” शामिल किया गया है।

NBFC की संपत्तियों की आंशिक क्रेडिट गारंटी के लिए केंद्र के प्रस्तावों और अपूर्ण आवासीय परियोजनाओं के अंतिम वित्त के लिए एक फंड को जल्दी से चालू करने की आवश्यकता है।

अक्टूबर मौद्रिक नीति का प्रबल संदेश यह था कि उदार रुख तब तक जारी रहेगा जब तक विकास बेहतर नहीं हो जाता है।



संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिहामी में सकल मूल्यवर्धित दर में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
2. सेवा क्षेत्र में हुई गिरावट वर्तमान मंदी का एक प्रमुख कारण है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements-

1. There has been 4.3 percent growth in Gross Value Added in the second by monthly report of current financial year.
2. The fall in the service sector is one of the main reason for the current slowdown.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) None of the these

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी को दूर करने के लिए सरकार के समक्ष उपलब्ध संभावित उपायों की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

Review the possible measures available to the government to overcome the ongoing slowdown in the Indian economy. (250 words)

नोट : 4 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।